

[2017] 1 एस.सी.आर 876

उड़ीसा औद्योगिक संरचना

विकास निगम

बनाम

मैसर्स मेंस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2545/2017)

14 फरवरी, 2017

[अरुण मिश्रा और अमितावा रॉय, जे.जे.]

उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम अधिनियम, 1980 का धारा 33 – अपीलार्थी को किया गया अनुरोध-भूमि के आवंटन के लिए निगम (इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए)-निगम का राज्य सरकार से आवंटन की प्रक्रिया के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध राज्य ने कुछ शर्तों के अधीन सैद्धांतिक रूप से आवंटन को मंजूरी दी नियम और शर्तें-प्रस्तावित आबंटित व्यक्ति को भुगतान करना आवश्यक था। बीस छमाही समान किशतों में भूमि की लागत पट्टा विलेख का निष्पादन भूमि के आवंटन के लिए पूर्ववर्ती शर्त थी-पहली किस्त जमा करने पर निगम द्वारा भूमि के एक हिस्से का अग्रिम कब्जा प्रस्तावित आवंटनकर्ता को दिया गया था-पट्टा विलेख का निष्पादन भूमि के आवंटन के बाद भी नहीं किया गया था। भूमि पर कब्जा कर लिया गया-लगभग पाँच साल से अधिक समय के बाद, अपीलकर्ता-निगम ने भूमि की लागत के लिए बकाया चूक राशि जमा करने के लिए अंतिम सूचना दी-पट्टा विलेख को निष्पादित करने और चूक राशि का भुगतान करने में विफलता पर, भूमि का कब्जा भूमि को रद्द कर दिया गया था और निगम द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया था एक

किस्त के लिए जमा की गई राशि को भूमि के उपयोग और कब्जे और नुकसान के मुआवजे के लिए समायोजित किया गया था। फिर से शुरू होने के बाद, भूमि को तीसरे पक्ष को आवंटित कर दिया गया था-अदालत में कब्जा रद्द करने और भूमि को फिर से शुरू करने पर सवाल उठाया गया था-उच्च न्यायालय ने माना कि निगम ने सी. एल. का पालन नहीं किया था। 18 नीतिगत निर्णय जिसके तहत भूमि का कब्जा फिर से शुरू करने से पहले 3 महीने का नोटिस दिया जाना आवश्यक था और निगम को प्रस्तावित भूमि को पट्टे पर देने का निर्देश दिया गया था। आवंटित-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: एस के तहत। 33 , निगम निपटान कर सकता है राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो आवश्यक हैं-पट्टा-विलेख का निष्पादन भूमि के आवंटन के लिए पूर्ववर्ती शर्त थी-चूंकि पट्टा-विलेख का निष्पादन कभी नहीं किया गया था, इसलिए पट्टाधारक-पट्टेदार का संबंध कभी अस्तित्व में नहीं आया-इस प्रकार सी.एल. 18 नीतिगत निर्णय कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि कोई निष्कर्षित अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया और लेन-देन अमान्य हो गया-इसलिए, सेवा देना आवश्यक नहीं है भूमि को फिर से शुरू करने और फिर से शुरू करने से पहले तीन महीने का नोटिस उचित था भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए राशि की जब्ती और नुकसान के लिए भी उचित था क्योंकि मुआवजे का दावा किया जा सकता था। 70 अनुबंध अधिनियम-मामले के तथ्यों में, प्रतिभूति रोक का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है क्योंकि निगम द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था-रूपये की लागत। 5 प्रत्यर्थी (प्रस्तावित आवंटित) पर लगाए गए लाख-अनुबंध अधिनियम, 1872। 70 प्रशासनिक कानून-प्रोमिसरी विबंध का सिद्धांत।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. जैसा कि उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 33 में प्रावधान किया गया है, निगम राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन भूमि का निपटान इस तरह से और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन कर सकता है जो आवश्यक हो। आवंटन पत्र में स्वयं पट्टा विलेख के एक शर्त रूप में निष्पादित करने का विचार कर सकता है। पूर्ववर्ती सामान्य नियमों और शर्तों की शर्त संख्या 18 पट्टा विलेख में अंतःस्थापित किया जाना बशर्ते कि पट्टेदार को नोटिस के बाद तीन महीने के भीतर उल्लंघन को ठीक करें। कहा जा चुका है शर्त संख्या 18 कभी लागू नहीं हुई और बनी रही। निष्क्रिय तत्काल मामले के तथ्यों में क्योंकि पट्टा विलेख स्वयं निष्पादित नहीं किया गया था। अन्यथा भी, मेंस्को (प्रतिवादी-प्रस्तावित आवंटी) को सुधार के लिए तीन महीने से अधिक का समय दिया गया था। उल्लंघन के रूप में फिर से शुरू करने के लिए नोटिस शुरू में दिया गया था 1997 और जुलाई, 2003 में फिर से शुरू होने तक साढ़े पाँच साल से अधिक समय तक, पट्टा विलेख हालांकि पट्टा विलेख का मसौदा जनवरी में भेजा गया था, 1996 निष्पादन के लिए। पट्टा विलेख के निष्पादन के अभाव में पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध कभी अस्तित्व में नहीं आया। पट्टा विलेख का निष्पादन आवश्यक था क्योंकि राज्य सरकार केवल सैद्धांतिक अनुमोदन दिया था और सलाह दी थी। भूमि का अग्रिम कब्जा मेंस्को को सौंप दिया है पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना। इस प्रकार, कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ। अस्तित्व में आया और एक औपचारिक पट्टा विलेख निष्पादित करने में मेंस्को की ओर से विफलता के कारण लेनदेन शून्य हो गया, और इसलिए, तीन महीने का नोटिस देना आवश्यक नहीं था कि दरार को ठीक करें। [पैरा 12, 13] [885-एफ-जी; 886-ई-एच; 887-ए-बी; 888-सी-डी]

2. निगम एक वैधानिक प्राधिकरण है और यह केवल लिखित पट्टा विलेख के आधार पर कार्य कर सकता है। पट्टे का निष्पादन विलेख आवश्यक है और यह

सार्वजनिक हित में है कि इसकी ओर से संपत्ति को अनधिकृत रूप से पट्टे पर देने से रोका जाए। पट्टे को औपचारिक दस्तावेज़ के रूप में एक निर्धारित प्रारूप में निष्पादित किया जाना आवश्यक है जो अनिवार्य नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में, पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध अस्तित्व में आने की अनुमति नहीं होगी। [पैरा 15] [889-बी]

भीकराज जयपुरिया बनाम। भारत संघ एआईआर 1962 एससी 113:  
[1962] एससीआर 880 पर भरोसा किया।

3. मेंस्को ने बिना कब्जा का आनंद लिया गया था। वर्ष 1997 में इसे फिर से शुरू करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद जुलाई 2003 तक निगम या मेंस्को ने कुछ नहीं किया। एक भी संवाद नहीं हुआ है। मेंस्को द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया जिसमें उल्लंघन को ठीक करने का प्रस्ताव है। मेंस्को की ओर से निष्क्रियता के लिए कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं किया गया है। मेंस्को की अपनी चूक और लापरवाही के कारण लेन-देन अमान्य हो गया और इसने पट्टा विलेख को निष्पादित करने का अधिकार खो दिया है। कब्जा करने के बाद, यह इतने वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता था। मेंस्को द्वारा जो किया जाना आवश्यक था वह नहीं किया गया था। यह भूमि पर मूल्य का कोई विकास करने में भी विफल रहा। इस निवेदन में कोई बल नहीं है कि उन्होंने Rs.22 करोड़ की राशि खर्च की है क्योंकि वे यह बताने में असमर्थ थे कि उन्होंने उक्त राशि कैसे खर्च की। इसके अलावा, पट्टा विलेख को निष्पादित करने में विफल रहने के कारण, उन्हें अपने जोखिम पर निवेश करना था। यदि उन्होंने कुछ राशि का निवेश किया है, तो उस आधार पर वे किसी कानूनी या न्यायसंगत अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। [पैरा 14] [888-ई-एच]

4. 1.25 करोड़ रुपये की राशि का ज़ब्त मेंस्को से भी उचित था। अनुबंध अधिनियम की धारा 70 से संबंधित है ऐसे मामले जहां कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है

जिसका कोई इरादा स्वेच्छा से कार्य करने का नहीं होता है और दूसरों को इसका आनंद मिलता है। ऐसी स्थिति में धारा 70 के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है। मेंस्को ओरिसा औद्योगिक इन्फ्रा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, इतने लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने के लिए मुआवजा। [पैरा 16] [889-एफ-एच; 890-ए]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मैसर्स बी.के. मंडल एंड संस ए.आई.आर 1962 एससी 779: [1962] पूरक। एससीआर 876; न्यू मरीन कोल कं. (बंगाल) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एआईआर 1964 एससी 152: [1964] एससीआर 859; ललितेश्वर प्रसाद साही बनाम बटेश्वर प्रसाद और अन्य एआईआर 1968 एससी 580; करमशी जेठाभाई सोमय्या बनाम बॉम्बे राज्य (अब महाराष्ट्र) एआईआर 1964 एससी 1714: [1964] एससीआर 984; मुलमचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1968 एससी 1218: [1968] एससीआर 214 - पर भरोसा किया।

5. उच्च न्यायालय ने पट्टा विलेख के निष्पादन का निर्देश देते हुए एक टालने योग्य अवैधता का साहस किया है। यह एक स्थापित कानून है कि इक्विटी ऐसे अनुबंधों के संबंध में सामान्य कानून के नियम का पालन करती है। पट्टे का नवीनीकरण एक विशेषाधिकार है और यदि कोई किरायेदार विशेषाधिकार का दावा करना चाहता है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए सीमित समय के भीतर सख्ती से ऐसा करना चाहिए। जहां कोई समय सीमा नहीं है, वहां उचित समय के भीतर आवेदन किया जा सकता है। यदि विलंब पट्टेदार की ओर से है। उसकी ओर से केवल उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले नवीनीकरण के लिए और जिसे उचित परिश्रम से टाला जा सकता था, उसे

नवीनीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं देगा। तत्काल मामले में एक ही सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि मेंस्को का आचरण अनुचित और अक्षम्य था। आचरण ने इसे किसी भी तरह से न्यायालय द्वारा संलिप्तता से वंचित कर दिया। [पैरा 18] [892-ए-सी]

6. मेंस्को के पास कोई राहत देने का कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं था। केवल कब्जे पर कब्जा करके। मेंस्को को करना आवश्यक था इस मामले में सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार कई कार्य किए गए जिनके अधीन पट्टा दिया जाना था। किशतों आदि के भुगतान सहित कुछ भी नहीं किया गया है और इस तरह ऐसी स्थिति में कोई राहत देने की अनुमति नहीं है। [पारस 19, 20] [892 डी-ई; 894-बी-सी]

खेला बनर्जी और अन्य बनाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और अन्य (2012) 7 एससीसी 261; विधिक प्रतिनिधि द्वारा राज किशोर (मृत) बनाम प्रेम सिंह और अन्य (2011) 1 एससीसी 657 [2010] 14 एससीआर 1019; मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी ढक्कन बनाम गोल्डन चैरियट एयरपोर्ट एंड अन्य (2010) 10 एससीसी 422: [2010] 12 एस. सी. आर. 326-निर्भर।

7. मेंस्को की यह दलील कि निगम प्रतिभूति रोक द्वारा बाध्य है, स्वीकृति के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। यह मेंस्को का मामला नहीं है कि उस पर कोई आश्वासन दिया गया था जिसके आधार पर उसने कार्य किया है। राज्य सरकार ने आवंटन का आदेश जारी होने से पहले ही 1 करोड़ रुपये की इक्विटी भागीदारी के अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को वापस ले लिया था। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि निगम पट्टा विलेख के निष्पादन के अधीन 2500 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। ऐसी स्थिति में प्रोमिसरी एस्टोपल की याचिका पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने

किसी भी समय, पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना, मेंस्को को कुछ भी करने के लिए कहा हो। इस तरह के किसी भी आश्वासन का कोई परिणाम नहीं होगा, भले ही वह दिया गया हो। तत्काल मामले के तथ्यों में, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है। निगम एक सांविधिक निकाय है और केवल निर्धारित तरीके से कार्य कर सकता है और मेंस्को को निर्धारित प्रारूप में निष्पादित किए जाने वाले पट्टा विलेख के बारे में सूचित किया गया था। [पैरा 21] [894 जी-एच; 895-ए-डी]

8. उच्च न्यायालय ने निर्देश देने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है बची हुई भूमि को पट्टे पर देना। उच्च न्यायालय ने भी अनदेखी की है कि कुछ मध्यवर्ती घटनाएं हुई हैं और मेंस्को की ओर से अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से विफलता थी। द. उच्च न्यायालय बदली हुई स्थिति और मेंस्को द्वारा किए गए चूक को देखते हुए इससे अधिक निर्देश जारी नहीं कर सकता था। वास्तव में, मेंस्को कभी भी दिनांकित 4.7.2003 पत्र की शर्तों का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं था। जब 25.7.2003 पर फिर से शुरू किया गया था, तो 20.8.2003 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था मेंस्को। इसमें, भुगतान के लिए प्रार्थना की आड़ में अपनी शर्तें निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। वास्तव में, मेंस्को के आचरण से यह स्पष्ट है कि इसका किसी भी समय कोई औचित्य नहीं था। पट्टा विलेख निष्पादित न करने का समय। यह उन कारणों के लिए देरी कर रहा था जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता था जो पूरी तरह से अस्वीकार्य आचरण था, विशेष रूप से कब्जा करने के बाद। उल्लंघन को कई वर्षों तक ठीक नहीं किया गया था, बहुत कम तीन महीनों के लिए जिसमें इसे ठीक किया जाना था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने भूमि को फिर से शुरू करने की निगम की कार्रवाई को अवैध ठहराने का दुस्साहस किया। इसमें प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई न्यायसंगत या कानूनी विचार नहीं था और अवैधता को कायम रखने के लिए एक रिट जारी नहीं की गई है। न केवल मेंस्को का आचरण

अनुचित था, बल्कि थर्ड पार्टी ओरिजा इंडस्ट्रियल इन्फ्रा, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वी. एम/एस। मेंस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड। अधिकारों ने भी हस्तक्षेप किया था। वैध विधि का प्रयोग किया गया था भूमि को फिर से शुरू करने और कब्जा सौंपने के पत्र को रद्द करने के लिए। [पैरा 23] [895-एफ-एच; 896-ए-बी]

#### मामला कानून संदर्भ

[1962] एससीआर 880	उस पर भरोसा करें	पैरा 15
[1962] पूरक। एससीआर 876	उस पर भरोसा करें	पैरा 16
[1964] एससीआर 859	उस पर भरोसा करें	पैरा 16
एआईआर 1968 एससी 580	उस पर भरोसा करें	पैरा 17
[1964] एससीआर 984	उस पर भरोसा करें	पैरा 17
[1968] एससीआर 214	उस पर भरोसा करें	पैरा 18
(2012) 7 एससीसी 261	उस पर भरोसा करें	पैरा 19
[2010] 14,एससीआर 1019	उस पर भरोसा करें	पैरा 20
[2010] 12 एससीआर 326	उस पर भरोसा करें	पैरा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2545/2017

साथ

आपराधिक अपील संख्या 2546 और 2547/2017

न्यायालय का निर्णय अरुण मिश्रा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।



2. इन अपीलों को उड़ीसा औद्योगिक ने प्राथमिकता दी है। अवसंरचना विकास निगम (संक्षेप में 'आईडीसीओ') और इसके द्वारा भी विवादित फैसले और दिनांकित आदेश से जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड व्यथित है। 30.10.2007 उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आईडीसीओ को 825.68 एकड़ भूमि पट्टे पर देना और पट्टा मैसर्स मेंस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड के साथ समझौता करने का निर्देश दिया गया।

3. तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है कि मेंस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड (संक्षेप में मेंस्को) ने 30.6.1994 पर भूमि और बदले में आईडीसीओ ने उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया। आवंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक आदेश जारी करना। 28.10.1994 पर राज्य सरकार ने 2500 के आवंटन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नीतिगत निर्णय में निर्धारित नियमों और शर्तों पर एकड़ भूमि राज्य सरकार की स्थापना के लिए 25.1.1995 पर संशोधित इस्पात संयंत्र।

4. प्रारंभ में राज्य सरकार भूमि की लागत के लिए 25 करोड़ रुपये की इक्विटी भागीदारी के लिए सहमत हुई थी। यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 2.2.1995 को वापस ले लिया गया और मेंस्को को सूचित किया गया। आईडीसीओ ने 21.3.1995 को मेंस्को को जमीन की कीमत बीस छमाही समान किस्तों में जमा करने के लिए एक पत्र लिखा और पहली किस्त के लिए 1.25 करोड़ रुपये और पहली किस्त के लिए 1.25 करोड़ रुपये जमा करने का अनुरोध किया। भूमि किराया और उपकर के लिए 13.08 लाख। मेंस्को ने 3.4.1995 को आईडीसीओ के पास 1.25 करोड़ रुपये जमा किये। 13.6.1996 को आईडीसीओ ने मेंस्को से पहले चरण में 1756.29 एकड़ भूमि का कब्जा लेने और निष्पादन के लिए मसौदा पट्टा विलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। मेंस्को ने 18.6.1996 को जमीन पर कब्जा कर लिया। हालाँकि, पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। इसके बाद, 13.10.1997 को, राज्य सरकार ने 26.9.1997 को

आयोजित बैठक की कार्यवाही की जानकारी आईडीसीओ को दी और उससे मेंस्को के पक्ष में लीज डीड निष्पादित करने और देय किस्तों की वसूली करने को कहा।

5. 27.10.1997 को, आईडीसीओ ने मेंस्को से 15 दिनों के भीतर निष्पादन के लिए पट्टा समझौते का मसौदा विलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, अन्यथा आवंटन रद्द करने और भूमि को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आईडीसीओ ने 26.11.1997 को निष्पादन के लिए समझौते का मसौदा विलेख प्रस्तुत करने के लिए फिर से अनुरोध किया। हालाँकि मेंस्को चुप रहा और लीज डीड प्राप्त करने में विफल रहा। निष्पादित। इसके बाद 5 साल से ज्यादा समय तक कुछ नहीं हुआ। मेंस्को द्वारा लीज डीड निष्पादित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद, आईडीसीओ ने 4.7.2003 को मेंस्को को वैधानिक बकाया राशि के साथ 22.44 करोड़ रुपये की शेष डिफॉल्ट राशि जमा करने और 19.7.2003 तक लीज डीड निष्पादित करने के लिए अंतिम नोटिस दिया, जिसमें विफल रहने पर यह सूचित किया गया कि उक्त भूमि को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उनकी लागत और भुगतान की गई राशि को भूमि के उपयोग और कब्जे के मुआवजे में समायोजित किया जाएगा, इसके अलावा, मेंस्को क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा। अंततः 25.7.2003 को लीज डीड निष्पादित कराने में विफल रहने पर, भूमि को फिर से शुरू कर दिया गया और 1756.29 एकड़ भूमि का कब्जा पत्र आईडीसीओ द्वारा रद्द कर दिया गया। मेंस्को द्वारा जमा की गई 1.25 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली गई और भूमि के उपयोग और कब्जे और क्षति के मुआवजे में समायोजित कर दी गई।

6. भूमि के पुनःग्रहण के बाद, आईडीसीओ ने 209.59 एकड़ जमीन आवंटित की 7.11.2003 को वीजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विचाराधीन भूमि से बाहर भूमि और साथ ही विवादित भूमि में से 71.20 एकड़ जमीन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को

आवंटित कर दी। भूमि का कब्जा वीजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंप दिया गया। 30.8.2004 को और 28.2.2005 को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को। आईडीसीओ को आगे आवंटित किया गया। 533.52 एकड़ विवादित भूमि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को और अन्य 120 विवादित भूमि में से एक एकड़ भूमि वीजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंप दी गई। क्रमशः 11.11.2005 और 17.11.2005 को जिंदल और वीजा को कब्जा दिया गया। उपरोक्त पक्षों के बीच लीज डीड आदि निष्पादित हो चुका है।

7. मेंस्को द्वारा 20.8.2003 को पुनः आरंभ पर सवाल उठाते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें मेंस्को ने भुगतान के लिए अपने स्वयं के नियम और शर्तें प्रस्तुत की थीं। उक्त अभ्यावेदन को आईडीसीओ द्वारा 26.9.2003 को खारिज कर दिया गया था। मुकदमेंबाजी का पहला दौर डब्ल्यू.पी. के रूप में। (सी) संख्या 12857/2003 मेंस्को द्वारा भूमि के रद्दीकरण और पुनःग्रहण पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने 15.1.2004 को उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इसके अनुसरण में, आईडीसीओ को प्रस्तुत दिनांक 20.1.2004 का अभ्यावेदन 25.2.2004 को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, मुकदमेंबाजी के दूसरे दौर में, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2453/2005, इसके लंबित रहने के दौरान, मेंस्को ने आईडीसीओ को दिनांक 22.8.2005 को एक और अभ्यावेदन दिया, जिसे 7.10.2005 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह अत्यधिक असंतोषजनक, असंबद्ध और पूरी तरह से अस्वीकार्य था। मेंस्को ने दिनांक 7.10.2005 के अस्वीकृति आदेश पर सवाल उठाने के लिए रिट याचिका में संशोधन किया। 11.4.2007 और 12.4.2007 को, उच्च न्यायालय ने फिर से आईडीसीओ से पूछा कि क्या वह शेष भूमि मेंस्को को पट्टे पर देने को तैयार है। चूंकि आईडीसीओ ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए उच्च न्यायालय ने 825.68 एकड़ भूमि को पट्टे पर देने के लिए रिट आवेदन की अनुमति दी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

8. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि आईडीसीओ ने दिनांक 25.1.1995 में नीतिगत निर्णय में निहित खंड 18 का अनुपालन नहीं किया है। जहाँ तक 3 महीने का नोटिस नहीं दिया गया है, यह कानून के उचित पाठ्यक्रम के अलावा कब्जे को फिर से शुरू करने के लिए खुला नहीं था। चूंकि मेंस्को ने अपनी याचिका को उपरोक्त सीमा तक उपलब्ध भूमि तक ही सीमित कर दिया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने 825.68 एकड़ भूमि को पट्टे पर देने के निर्देश जारी किए थे।

9. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने भूमि को फिर से शुरू करने के आदेश को रद्द करने में कानूनी रूप से लापरवाही की है क्योंकि वर्ष 1996 और 1997 में आईडीसीओ द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद पट्टा विलेख को निष्पादित करने में मेंस्को की ओर से विफलता हुई थी और उसके बाद कई वर्षों तक शांति रही और अंततः नोटिस जारी करने के बाद भूमि को फिर से शुरू किया गया था। जिसे बाद में अन्य उद्योगों को आवंटित कर दिया गया और शेष भूमि को उनके भविष्य के विस्तार के लिए आवश्यक था। खनन उद्देश्यों के लिए भूमि वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं है। किशतें भी जमा नहीं की गईं। पट्टा विलेख के निष्पादन के अभाव में, पट्टेदार का संबंध और पट्टेदार कभी अस्तित्व में नहीं आया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए 3 महीने का नोटिस भूमि की आवश्यकता नहीं थी। पट्टा विलेख समाप्त करने के लिए तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। पुनः आरंभ करने का आदेश पारित किया गया और उसके अनुसार, अधिकार उचित रूप से ले लिया गया है क्योंकि मेंस्को के पास कोई अधिकार नहीं था। किशतों का भुगतान करने और पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहने पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार। आईडीसीओ द्वारा रुपये की राशि जमा करने के लिए आदेश पारित किया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 1.25

करोड़ रुपये पूरी तरह से उचित थे। मेंस्को द्वारा विचाराधीन भूमि पर कोई विकास नहीं किया गया था। इस प्रकार, विवादित आदेश को अलग रखा जा सकता है।

10. अपील में हस्तक्षेप किया जाता है। इस्पात संयंत्र की स्थापना राज्य और बड़े पैमाने पर जनता के हित में होगी। कुछ कानूनी कार्यवाही आदि के कारण, मेंस्को पट्टा विलेख को निष्पादित नहीं कर सका। भूमि को फिर से शुरू करने के लिए 3 महीने का नोटिस देना आवश्यक था। किया गया। भूमि पर विकास के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर, यह कहा गया कि चारदीवारी का निर्माण किया गया था। हालांकि, फिर से शुरू होने से पहले कोई संयंत्र आदि स्थापित नहीं किया जा सका।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विस्तार करने से पहले, यह उचित है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दें। उड़ीसा सरकार, इस्पात और खान विभाग ने 3 मिलियन टन प्रति वर्ष की अंतिम क्षमता के साथ 2 मिलियन टन स्टील संयंत्र की स्थापना के लिए 2500 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। रुपये की इक्विटी भागीदारी के लिए प्रस्ताव. आवंटन के लिए निर्देश जारी होने से पहले राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 5.1.1995 के माध्यम से 25 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए और आईडीसीओ को 2500 एकड़ भूमि दीर्घकालिक पट्टे पर सौंपने की सलाह दी गई। 25.1.1995 को सरकार द्वारा जारी संशोधित नियमों और शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर। उन्हें रुपये जमा करने थे। पहली किस्त के लिए 1.25 करोड़ रु. 13,08,842/- भूमि किराया और उपकरण के रूप में, जैसा कि पत्र दिनांक 21.3.1995 में दर्शाया गया है। रुपये की राशि. 3.5.1995 को 1.25 करोड़ रुपये जमा किये गये। आईडीसीओ के दिनांक 13.6.1996 के संचार के अनुसार, 1756.29 एकड़ भूमि का कब्जा लेने की आवश्यकता थी और मेंस्को को दो प्रतियों में समझौते का एक मसौदा विलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, ऐसा प्रतीत होता है कि 18.6.1996 को 1756 एकड़ भूमि का

अग्रिम कब्जा कर लिया गया था। मेंस्को को सौंप दिया गया था लेकिन लीज डीड के निष्पादन के लिए समझौते का मसौदा दस्तावेज उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए 27.10.1997 को एक पत्र लिखा गया था।आईडीसीओ द्वारा भूमि को फिर से शुरू करने और आवंटन को रद्द करने के लिए। दिनांक 26.11.1997 को भेजे गए पत्र में, आईडीसीओ ने लिखा कि उसने 20.1.1996 को मेंस्को को पट्टा विलेख का मसौदा भेजा था और मेंस्को को तुरंत निष्पादन के लिए पट्टा समझौते का मसौदा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालांकि कब्जा मेंस्को हट द्वारा ले लिया गया था, उसी समय, लीज डीड को निष्पादित करने में उसकी ओर से बेवजह उपेक्षा की गई थी। कई वर्षों तक मेंस्को की ओर से गंभीर चूक के कारण लीज डीड निष्पादित नहीं की जा सकी। अंततः आईडीसीओ ने भूमि को फिर से शुरू करने के संबंध में मेंस्को को दिनांक 4.7.2003 को नोटिस दिया था, जिसमें लीज डीड निष्पादित करने या भूमि की बहाली का सामना करने के लिए अपने पहले के संचार दिनांक 27.10.1997 और 26.11.1997 का हवाला दिया गया था। शुरुआती रकम 1.25 करोड़ रुपये के अलावा किशतों की रकम भी जमा नहीं की गई थी. इस प्रकार मेंस्को को नोटिस द्वारा शेष डिफॉल्ट राशि रुपये 22,84,48,890/- जमा करने की आवश्यकता थी और पट्टा विलेख को 19.7.2003 तक निष्पादित करना होगा, ऐसा न करने पर भूमि को फिर से शुरू कर दिया जाएगा और मेंस्को द्वारा भुगतान की गई राशि को भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे में समायोजित किया जाएगा और भविष्य में नुकसान की देनदारी होगी और उसके बाद की लागत। चूँकि मेंस्को द्वारा कुछ नहीं किया गया, दिनांक 25.7.2003 के संचार के माध्यम से, आईडीसीओ ने भूमि को फिर से शुरू कर दिया और दिनांक 18.6.1996 को कब्जे के विलेख की डिलीवरी रद्द कर दी। जमा की गई धनराशि जब्त कर ली गई।

12. उड़ीसा सरकार और मेंस्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच 4.5.1994 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। उसी के अनुसार, उड़ीसा सरकार ने उपयुक्त खनन स्थानों पर खनन के लिए पट्टा अधिकार की सिफारिश करने का बीड़ा उठाया था। एमओयू को नियत समय में समझौते में बदलने की आवश्यकता थी। द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार उड़ीसा सरकार ने इस्पात संयंत्रों के लिए भूमि के आवंटन के लिए प्रति एकड़ भूमि की लागत 1 लाख रुपये रखी थी। इस राशि का भुगतान किशतों में किया जाना था जैसा कि नष्ट की गई संपत्ति को 90 वर्षों तक रखने के अधिकार के साथ प्रदान किया गया था। सम्मिलित किए जाने वाले सामान्य नियमों और शर्तों की शर्त संख्या 18 पट्टा विलेख में यह प्रावधान किया गया है कि पट्टेदार को नोटिस के बाद तीन महीने के भीतर उल्लंघन का समाधान करना होगा। सामान्य नियमों और शर्तों का खंड 18 यहाँ नीचे निकाला गया है:

"18. यदि पट्टेदार का बकाया इसके द्वारा आरक्षित है या कोई हिस्सा उसका किसी भी समय उस तारीख के बाद अगले तीन महीने के लिए बकाया और अवैतनिक होने पर, जिस दिन वह देय हो गया होगा, चाहे उसकी कानूनी रूप से मांग की गई हो या नहीं, या यदि अनुच्छेद का उल्लंघन या पालन न किया गया हो। पट्टेदार द्वारा लिखित सूचना दी जाती है या दिवालिया हो जाता है या रचना के लिए अपने लेनदारों के साथ एक समझौता करता है उक्त व्यवसाय से। इस समझौते को माना जाएगा कि पट्टे के तहत बकाया की वसूली के लिए, समाप्त पर दर्ज करें संपत्ति और उसी पर कब्जा करें जैसे कि इस नष्ट संपत्ति के पास था पट्टे पर नहीं दिया गया। ऐसे मामले में पट्टेदार को भुगतान करना होगा हानि या ऐसे अन्य शुल्कों के रूप में ऐसी राशि को कम करें। जैसा कि छोटे द्वारा निर्धारित किया जा

सकता है। नुकसान की राशि या पट्टेदार से वसूल किए जाने वाले अन्य बकाया को उसके खिलाफ समायोजित किया जाएगा। पट्टेदार द्वारा पहले से ही भुगतान की गई राशि। यदि इस तरह के समायोजन के बाद वहाँ अधिशेष रहता है, वही पट्टेदार को वापस कर दिया जाएगा बिना किसी के ब्याज। यदि इस तरह के समायोजन के बाद वहाँ रहेगा पट्टेदार से वसूली योग्य कुछ देय राशि और यदि पट्टेदार भुगतान करने में विफल रहता है उसी प्रकार, पट्टेदार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जोर दिया गया)

एहसास के लिए लगता है कथित "शर्त संख्या 18 कभी लागू नहीं हुई और बनी रही। तत्काल मामले के तथ्यों में निष्क्रिय क्योंकि पट्टा विलेख स्वयं निष्पादित नहीं किया गया था। अन्यथा भी, उल्लंघन को ठीक करने के लिए मेंस्को को तीन महीने से अधिक का समय दिया गया था क्योंकि शुरुआत में 1997 में फिर से शुरू करने के लिए नोटिस दिया गया था और जुलाई, 2003 में फिर से शुरू होने तक साढ़े पांच साल से अधिक समय तक उल्लंघन को ठीक नहीं किया गया था। अग्रिम कब्जा प्राप्त करने के बावजूद, मेंस्को की ओर से पट्टा विलेख को निष्पादित करने में विफलता हुई, हालांकि पट्टा विलेख का मसौदा जनवरी, 1996 में निष्पादन के लिए भेजा गया था। पट्टा विलेख के निष्पादन के अभाव में पट्टेदार और पट्टेदार का संबंध कभी अस्तित्व में नहीं आया। पट्टा विलेख का निष्पादन आवश्यक था क्योंकि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और आईडीसीओ को भूमि आवंटित करने की सलाह दी थी जो केवल पट्टा विलेख के निष्पादन द्वारा की जा सकती थी। वास्तव में, आईडीसीओ को पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना भूमि का अग्रिम कब्जा मेंस्को को नहीं सौंपना



चाहिए था। हालांकि, आईडीसीओ को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, अग्रिम कब्जा दिया गया था। आवंटन पत्र ने स्वयं पट्टा विलेख के निष्पादन को एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में माना। जैसा कि उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 33 में प्रदान किया गया है (ओरिशा औद्योगिक इन्फ्रा के लिए। संक्षिप्त में 'अधिनियम'), निगम राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन भूमि का निपटान इस तरह से और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन कर सकता है जो आवश्यक हो। यह है शर्त लीज डीड के निष्पादन का उदाहरण था, और जैसा कि राज्य सरकार द्वारा भी ऐसा निर्देश दिया गया था, हमारी सुविचारित राय में, कोई निष्कर्षित अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया और औपचारिक केस डीड को निष्पादित करने में मेंस्को की विफलता के कारण लेनदेन अमान्य हो गया।

13. अधिनियम की धारा 33 यहाँ नीचे निकाली गई है:

"धारा 33। निगम द्वारा भूमि का निपटान - (1) राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन निगम निपटान कर सकता है -

(क) राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित और उसे हस्तांतरित की गई कोई भी भूमि, बिना किसी उपक्रम या किसी विकास को अंजाम दिए। उस पर; या

(ख) ऐसी कोई भी भूमि, ऐसा उपक्रम करने या उसे पूरा करने के बाद विकास जैसा वह उचित समझता है,

ऐसे व्यक्ति को इस तरह से और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो वह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समीचीन समझता है। इस अधिनियम से।

(2) उप-एस के तहत भूमि के निपटान के संबंध में निगम की शक्तियां। (1)

जहां तक संभव हो, इस तरह से सुरक्षित किया जाएगा कि -

(अ) जहाँ निगम किसी भी वस्तु को बिक्री द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करता है। ऐसी भूमि जो उसकी आवश्यकता के लिए अधिशेष है, निगम पहली बार में उन व्यक्तियों को भूमि की पेशकश करेगा जिनसे वह अधिग्रहित की गई थी, यदि वे इसे खरीदना चाहते हैं, बशर्ते कि: इसके विकास और उपयोग के लिए ऐसी आवश्यकताएँ निगम लागू करना उचित समझ सकता है।

(बी) ऐसे व्यक्ति जो रह रहे हैं या व्यवसाय या अन्य कार्य कर रहे हैं। ऐसी किसी भी भूमि पर गतिविधियाँ, यदि वे निगम से संबंधित भूमि पर आवास प्राप्त करना चाहते हैं और निगम की किसी भी आवश्यकता का पालन करने के लिए तैयार इसके विकास और उपयोग के लिए प्राप्त करने का अवसर है। उन पर उनके उचित के लिए उपयुक्त आवास। कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की गई शर्तों पर आवश्यकताएँ जो ऐसी कोई भी भूमि उनसे अधिग्रहित की गई हो।

(3) इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निगम को उपहार के रूप में भूमि का निपटान करने में सक्षम बनाती है, लेकिन उपरोक्त के अधीन रहते हुए; इस अधिनियम में भूमि के निपटान के लिए दिए गए निर्देश का अर्थ किसी भी मामले में उसके निपटान के संदर्भ के रूप में किया जाएगा। बिक्री, बंधक, विनिमय या पट्टा के माध्यम से या किसी मामले, अधिकार या विशेषाधिकार के निर्माण के माध्यम से या अन्यथा।"

धारा 33 (1) और 33 (3) से यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक था। पट्टा विलेख को निष्पादित करने के लिए क्योंकि निगम भूमि का निपटान केवल उसी तरीके से कर सकता था जैसा कि कानून में प्रावधान किया गया है और अन्यथा भी ऐसा ही था सरकारी आदेश में ही निर्दिष्ट। इस प्रकार, मेंस्को की उपेक्षा के कारण लेन-देन अमान्य हो गया और तीन की सेवा देना आवश्यक नहीं था। उल्लंघन को ठीक करने के लिए महीनों का नोटिस। हालांकि, कई वर्षों तक मामले के तथ्यों में संचार के बाद उल्लंघन को ठीक नहीं किया गया था दिनांक 27.10.1997 जुलाई, 2003 तक।

14. तत्काल मामले में यह स्पष्ट है कि पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना मेंस्को द्वारा कब्जे का आनंद लिया गया था। का आचरण आईडीसीओ भी मेंहनती नहीं था। वर्ष 1997 में इसे फिर से शुरू करने के लिए सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बाद जुलाई 2003 तक आईडीसीओ या मेंस्को ने कुछ नहीं किया। मेंस्को द्वारा एक भी संचार को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जिसमें उल्लंघन को दूर करने के उसके प्रस्ताव को शामिल किया गया है और मेंस्को की ओर से पेश विद्वान वकील से एक विशिष्ट प्रश्न किए जाने पर, वे यह समझाने में असमर्थ थे कि 1997 और 2003 के बीच क्या हुआ, सिवाय एक अस्पष्ट प्रस्तुतिकरण के कि यह कुछ मुकदमों में फंसा हुआ था, जिसका तथ्य भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार, मेंस्को की ओर से निष्क्रियता के लिए कोई स्पष्टीकरण, अच्छा, बुरा या अन्यथा रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। मेंस्को की अपनी चूक और लापरवाही के कारण लेन-देन अमान्य हो गया और इसने पट्टा विलेख को निष्पादित करने का अधिकार खो दिया है। कब्जा करने के बाद, यह इतने वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता था। मेंस्को द्वारा जो किया जाना आवश्यक था वह नहीं किया गया था। यह भी। भूमि पर मूल्य का कोई विकास करने में विफल रहा। हम इस निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि उन्होंने Rs.22 करोड़ की राशि खर्च की है क्योंकि उन्होंने वे यह समझाने में असमर्थ थे कि उन्होंने उक्त राशि कैसे खर्च की, और केवल

एक गंजा बयान दिया गया कि उन्होंने एक चारदीवारी का निर्माण किया है। इसमें है। यह स्थापित नहीं किया गया है कि मेंस्को द्वारा रुपये 22 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। इसके अलावा, पट्टा विलेख को निष्पादित करने में विफल रहने के कारण, वे ORISSA औद्योगिक इन्फ्रा के लिए थे। अपने जोखिम पर निवेश करें। यदि उन्होंने कुछ राशि का निवेश किया है, तो उस आधार पर वे किसी कानूनी या न्यायसंगत अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

15. आईडीसीओ एक सांविधिक प्राधिकरण है और यह केवल लिखित पट्टा विलेख के आधार पर कार्य कर सकता है। पट्टा विलेख का निष्पादन आवश्यक है और यह है उसकी ओर से संपत्ति को अनधिकृत रूप से पट्टे पर देने से रोकने के लिए जनहित में। पट्टे को औपचारिक दस्तावेज के रूप में एक निर्धारित प्रारूप में निष्पादित किया जाना आवश्यक है जो अनिवार्य नहीं है। इसके अभाव में पट्टेदार और पट्टेदार के उस संबंध को बनाए रखने की अनुमति नहीं होगी। अस्तित्व में आया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175 (3) के तहत एक स्थिति उत्पन्न हुई जिसे निष्पादित करने के लिए एक औपचारिक दस्तावेज की आवश्यकता थी, जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 299 के समान था, इस न्यायालय ने भिकराज जयपुरिया बनाम भारत संघ एआईआर 1962 एससी 113 के लिए सरकारी और निजी व्यक्तियों के बीच अनुबंध, औपचारिक दस्तावेज आवश्यक है और जहां यह आवश्यक है कि एक काम में किया जाएगा निर्धारित विधि या प्रपत्र लेकिन गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्धारित नहीं करता है, यह प्रश्न कि क्या प्रावधान अनिवार्य था या निर्देशिका को विधायिका के इरादे के आलोक में आंका जाना है जैसा कि उद्देश्य द्वारा प्रकट किया गया है। यदि कानून के प्रावधान अनिवार्य हैं, तो निर्धारित तरीके या रूप में नहीं की गई चीज का कोई प्रभाव या वैधता नहीं हो सकती है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि यह जनता के हित में है कि यह सवाल कि क्या राज्य और एक निजी व्यक्ति के

बीच एक बाध्यकारी अनुबंध किया गया है, विवाद और मुकदमेंबाजी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि निगम के साथ पट्टा विलेख को निष्पादित करने का एक तरीका है।

पट्टा विलेख के प्रारूप का निर्धारित रूप था आईडीसीओ द्वारा मेंस्को को भेजा गया लेकिन यह इसे निष्पादित करने में विफल रहा। इस प्रकार, ऐसा कोई अनुबंध नहीं था जिसे लागू किया जा सकता था और इसके कारण यह अमान्य हो गया स्वयं मेंस्को की निष्क्रियता।

16. रुपये की राशि का ज़ब्त। 25 करोड़ भी उचित था। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मैसर्स बी. के. मंडल एंड संस एआईआर 1962 एससी 779, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 175 (3) का प्रावधान अनिवार्य है और गैर-अनुपालन अनुबंध को अमान्य बनाता है और अनुबंध अधिनियम की धारा 70 अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकती है। यह व्यक्तियों पर उतना ही लागू होता है जितना कि निगम और सरकार। अनुबंध अधिनियम की धारा 70 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है। जिसका कोई इरादा स्वेच्छा से कार्य करने का नहीं होता है और दूसरों को इसका आनंद मिलता है। ऐसी स्थिति में धारा 70 के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है और इस न्यायालय ने माना है कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 175 (3) अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ टकराव में नहीं है। इस प्रकार, हम में कोई बल नहीं पाते हैं। रुपये 1.25 करोड़ की राशि की जब्ती के संबंध में मेंस्को की ओर से प्रस्तुत करना। इसके अलावा, वे इतने लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। न्यू मरीन कोल कंपनी (बंगाल) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एआईआर 1964 एससी 152 भी, यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई अनुबंध के

प्रावधानों के कारण अमान्य पाया जाता है भारत सरकार अधिनियम की धारा 175 (3) यह अप्रवर्तनीय हो जाती है लेकिन यदि किसी पक्ष ने अपने दायित्व का पालन किया है, तो मुआवजे की वसूली के लिए धारा 70 लागू की जाती है।

17. ललितेश्वर प्रसाद साही बनाम बटेश्वर प्रसाद और ओआरएस। एआईआर 1968 एससी 580 जहां संविधान के अनुच्छेद 299 के उल्लंघन में केवल समझौता किया गया था और सरकार द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, इसे अनुबंध नहीं माना गया था क्योंकि यह अमान्य और अप्रवर्तनीय था। करमशी जेठाभाई में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है। सोमय्या वी. बॉम्बे राज्य (अब महाराष्ट्र) एआईआर 1964 एससी 1714। यह सच है कि उक्त प्रावधान तत्काल मामले में आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन सांविधिक निगम को भी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करना होता है।

18. ऐसे मामलों में रोक या अनुसमर्थन का कोई सवाल ही नहीं है। मुलमचंद बनाम। मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1968 एससी 1218, यह न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"6.....सिद्धांत यह है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175 (3) के प्रावधान या भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के संबंधित प्रावधान अनिवार्य हैं। चरित्र और इन प्रावधानों का उल्लंघन अनुबंधों को रद्द कर देता है और उन्हें अमान्य कर देता है। ऐसे मामले में रोक या अनुसमर्थन का कोई सवाल ही नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 175 (3) और संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के संबंधित प्रावधानों को केवल रूप के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है, लेकिन उनके पास है - आम जनता की सुरक्षा और इन औपचारिकताओं को नहीं किया जा सकता है माफ या वितरित किया गया। यदि निरोध या अनुसमर्थन के संबंध में प्रत्यर्थी की याचिका स्वीकार की जाती है, तो इसका मतलब प्रभावी रूप से

आम जनता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करना होगा। यही कारण है कि एस.ए. औद्योगिक इन्फ्रा की याचिका। या ऐसे मामले में अनुसमर्थन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर पैसा जमा किया जाता है और सामान की आपूर्ति की जाती है या अगर सेवाएं प्रदान की जाती हैं अमान्य अनुबंध की शर्तें, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के प्रावधान लागू हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस धारा के प्रावधानों को व्यथित पक्ष द्वारा अमान्य अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है। पहली शर्त यह है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए या उसे कुछ देना चाहिए; दूसरी शर्त यह है कि उक्त कार्य करने या उक्त कार्य को करने में उसे अनावश्यक रूप से कार्य करने का इरादा नहीं होना चाहिए; और तीसरी शर्त यह है कि दूसरा व्यक्ति जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है, उसे उसका लाभ उठाना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो धारा 70 बाद वाले व्यक्ति पर इस तरह से किए गए या वितरित किए गए कार्य के संबंध में पूर्व को मुआवजा देने या पुनर्स्थापित करने का दायित्व लगाती है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 70 के तहत आने वाले मामले में व्यक्ति जो दूसरे के लिए कुछ कर रहा है या दूसरे को कुछ वितरित कर रहा है, वह अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है, न ही अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग कर सकता है, इस सरल कारण से कि उसके और उस दूसरे व्यक्ति के बीच कोई अनुबंध नहीं है जिसके लिए वह कुछ करता है या जिसके लिए वह कुछ वितरित करता है। इसलिए जहां धारा 70 के तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ मुआवजे का दावा किया जाता है, वह पक्षों के बीच किसी भी मौजूदा अनुबंध के आधार पर नहीं है, बल्कि एक अलग तरह के दायित्व पर है। ऐसे मामले में दायित्व का न्यायिक आधार किसी अनुबंध या अपकृत्य पर आधारित नहीं है, बल्कि कानून की

तीसरी श्रेणी, अर्थात् अर्ध-अनुबंध पर आधारित है। या पुनर्प्राप्ति। बिबरॉसा वी. फेयरबेर्न, 1943 एसी 32 लॉर्ड राइट ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार बताया है:

"कानून की सभ्य प्रणाली उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य है किसी भी अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ कहे जाने वाले मामलों के लिए, यानी किसी व्यक्ति को धन रखने से रोकने के लिए किसी अन्य का, या उससे प्राप्त कुछ लाभ, जिसे उसे रखना चाहिए, वह विवेक के विरुद्ध है। अंग्रेजी में इस तरह के उपचार कानून सामान्य रूप से अनुबंध या अपकृत्य में उपचार से अलग हैं, और अब सामान्य कानून की तीसरी श्रेणी के भीतर आने के लिए मान्यता प्राप्त है जिसे अर्ध-अनुबंध या प्रतिपूर्ति।"

उपरोक्त निर्णय के आलोक में, जब हम तत्काल मामले में मेंस्को के समग्र आचरण पर विचार करते हैं, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं कि उच्च न्यायालय ने पट्टा विलेख के निष्पादन का निर्देश देते हुए एक टालने योग्य अवैधता का साहस किया है। यह एक स्थापित कानून है कि इक्विटी ऐसे अनुबंधों के संबंध में सामान्य कानून के नियम का पालन करती है। पट्टे का नवीनीकरण एक विशेषाधिकार है और यदि कोई किरायेदार विशेषाधिकार का दावा करना चाहता है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए सीमित समय के भीतर सख्ती से ऐसा करना चाहिए। इस न्यायालय ने आगे इस प्रश्न पर विचार किया है कि जहां कोई समय सीमा नहीं है, एक उचित समय के भीतर एक आवेदन किया जा सकता है। यदि नवीकरण के लिए पट्टेदार की ओर से देरी उसकी ओर से केवल उपेक्षा के कारण हो रही है और जिससे बचा जा सकता था उचित परिश्रम, उसे नवीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं देगा। तत्काल मामले में एक ही सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि मेंस्को का आचरण अनुचित और



अक्षम्य था। आचरण ने इसे किसी भी तरह से न्यायालय द्वारा संलिप्तता से वंचित कर दिया। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि कई बार उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और हर अवसर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार, मांगी गई राहतों के लिए रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए मेंस्को के पास कोई न्यायसंगत विचार उपलब्ध नहीं था। कानून के अनुसार दी गई राहत की अनुमति नहीं है।

19. मेंस्को के पास कोई भी राहत देने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं था केवल अधिकार सौंपना। यह सवाल इस अदालत के समक्ष खेला बनर्जी और अन्न मामले में आया। वी. सिटी मॉटेसरी स्कूल और ओआरएस। (2012) 7 एससीसी 261 जब बोली रद्द कर दी गई और स्वीकार नहीं की गई, लेकिन प्रत्यर्थी के प्रबंधक ने राज्यपाल को दस छह में शेष राशि के कब्जे और स्वीकृति का व्यक्तिगत आदेश पारित करने के लिए आश्वस्त किया। मासिक किश्तें; उसके बाद किश्तों का भुगतान नहीं किया गया। यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि दिनांकित समझौते के निष्पादन के बावजूद प्रत्यर्थी के पक्ष में अर्जित कोई भी प्रवर्तनीय अधिकार और प्रत्यर्थी द्वारा शेष मूल्य का भुगतान करने के लिए किए गए प्रस्ताव को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया है:

"29. पहला प्रश्न जो विचार करने योग्य है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर दर्ज किया गया निष्कर्ष दिनांकित 12-1-1996 समझौते की प्रवर्तनीयता सही है और शेष मूल्य को स्वीकार करने के लिए LDA को निर्देश जारी करने के लिए प्रतिवादी 1 की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। यह एक

स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 1 की निविदा सूचना के जवाब में, प्रतिवादी 1 ने प्लॉट संख्या 92-ए/सी सहित चार भूखंडों के लिए बोलियां दीं और उसके द्वारा प्रस्तावित मूल्य का 25 प्रतिशत भुगतान किया, लेकिन शेष राशि एसए औद्योगिक इन्फ्रा का भुगतान नहीं किया। बोली को रद्द करने की आवश्यकता, जिसके बारे में सूचना 14-6-1995 दिनांकित पत्र के माध्यम से दिया गया था। प्रत्यर्थी 1 ने उचित कानूनी उपाय का लाभ उठाकर बोलियों को रद्द करने को चुनौती नहीं दी, लेकिन इसके प्रबंधक को समझाने में सफल रहे राज्य के राज्यपाल भूखंडों का कब्जा सौंपने और शेष राशि को छह-मासिक किश्तों में स्वीकार करने के लिए एक असामान्य आदेश पारित करेंगे। जिन कारणों से राज्यपाल को कार्य के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित किया और प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में भूखंडों की बहाली का आदेश दिया, हालांकि बोलियों को रद्द करने के एलडीए के निर्णय को दरकिनार किए बिना इससे पहले प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है अदालत। इसलिए, हमारा मानना है कि राज्यपाल द्वारा पारित आदेश और राज्य सरकार और एल. डी. ए. द्वारा दिनांकित समझौते के निष्पादन सहित की गई परिणामी कार्रवाइयों ने प्रतिवादी 1 के पक्ष में एक प्रवर्तनीय अधिकार नहीं बनाया और उच्च न्यायालय ने शेष मूल्य के भुगतान के लिए अपनी ओर से किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए एलडीए को एक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

30. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 12-1-1996 दिनांकित समझौते में एक स्पष्ट शर्त थी कि यदि प्रत्यर्थी में निर्धारित समय

सीमा के भीतर शेष मूल्य की किशतों का भुगतान करने में विफल रहता हूं तो समझौता अमान्य हो जाएगा और एलडीए किसी अन्य व्यक्ति को भूखंड बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। मान लीजिए, प्रत्यर्थी 1 ने शेष मूल्य की किशतों का भुगतान नहीं किया। इसलिए, समझौता स्वचालित रूप से समाप्त हो गया और एलडीए एक उपयुक्त तंत्र को अपनाकर भूखंड के निपटान का हकदार बन गया। संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत के साथ। यह दिलचस्प है कि एलडीए के पदाधिकारी 13 वर्षों से अधिक समय तक चुप क्यों रहे और उन्होंने विचाराधीन भूखंड पर फिर से कब्जा क्यों नहीं किया। यह शायद उत्तरदाता 1 के प्रबंधक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्रों से लाए गए दबाव के कारण था।

XXX

XXX

XXX

32. हमने 2009 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान से देखा है और पाया है कि वे शैक्षणिक संस्थानों को भूमि के आवंटन के मुद्दे को दूर से भी नहीं निपटाते हैं। उच्च न्यायालय की खंड पीठ में बिल्कुल भी उचित नहीं था अपने स्वयं के निष्कर्ष की अनदेखी करते हुए कि उक्त प्रतिवादी एक श्रेणीबद्ध था चूककर्ता और रिट याचिका 13 के समय अंतराल के बाद दायर की गई थी। बिना किसी ठोस स्पष्टीकरण के वर्षों तक"।

(हमारे द्वारा जोड़ा गया जोर)

20. मेंस्को को इस मामले में कई कार्य करने की आवश्यकता थी सामान्य नियम और शर्तें जिनके अधीन पट्टा दिया जाना था। किशतों आदि के भुगतान सहित

कुछ भी नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में विधिक प्रतिनिधि द्वारा राज किशोर (मृत) बनाम प्रेम सिंह और अन्य (2011) एससीसी 657 मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कोई राहत देने की अनुमति नहीं है। जिसमें इस न्यायालय ने हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों का उल्लेख किया है। इस प्रकार:

"33. इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ निम्नलिखित को भी उद्धृत किया: हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम। 14, तृतीय संस्करण।, पी. 622, पैरा 1151:

"1151. शर्तों को एक सामान्य नियम के रूप में सख्ती से होना चाहिए देखा गया। जहाँ किसी अनुबंध, हस्तांतरण, या वसीयत के तहत एक द्वारा निष्पादन पर लाभकारी अधिकार उत्पन्न होना है किसी अधिनियम के लाभार्थी को निर्दिष्ट तरीके से, या किसी निर्दिष्ट तरीके से समय, अधिनियम प्राप्त करने के लिए तदनुसार किया जाना चाहिए अधिकार का आनंद, और धोखाधड़ी के अभाव में, दुर्घटना या आश्चर्य, इक्विटी एक उल्लंघन के खिलाफ राहत नहीं देगा शर्तों से।"

यह स्पष्ट है कि जब किसी कथन में कई कार्य किए जाने हैं। तरीके से और निर्धारित समय में और उनमें से कोई भी प्रदर्शन नहीं किया गया है, जैसा कि तत्काल मामले में, इस तरह का घोर उल्लंघन अपरिवर्तनीय हो गया और कोई भी न्यायसंगत सिद्धांत मेंस्को के बचाव में नहीं आ सकता था क्योंकि यह अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

21. मेंस्को की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि आईडीसीओ इसके लिए बाध्य है। वादा रद्द करना। हम प्रस्तुतिकरण को स्वीकृति के लिए पूरी तरह से अयोग्य पाते हैं। यह मेंस्को का मामला नहीं है कि कोई आश्वासन दिया गया था जिसे दिया

गया है, जिसके आधार पर उसने कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने Rs.25 करोड़ की इक्विटी भागीदारी के अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को वापस ले लिया था। आवंटन का आदेश जारी होने से बहुत पहले। आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकार ने आईडीसीओ को 2500 एकड़ उडीसा औद्योगिक इन्फ्रा आवंटित करने का निर्देश दिया था। पट्टा विलेख के निष्पादन के अधीन भूमि। ऐसी स्थिति में प्रोमिसरी एस्टोपल की याचिका पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने किसी भी समय, पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना, मेंस्को को कुछ भी करने के लिए कहा हो। इस तरह का कोई भी आश्वासन, भले ही दिया गया हो, कोई परिणाम नहीं देगा जैसा कि इस न्यायालय ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी लिमिटेड बनाम स्वर्ण रथ हवाई अड्डा में अभिनिर्धारित किया है। और अन्य (2010) 10 एससीसी 422। इसमें एक सवाल उठा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन इसके तहत किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1944 की धारा 3 को अधिनियम और विनियमों के तहत प्रदान किए गए एक विशेष रूप में अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही मौखिक आश्वासन लाइसेंस का निष्पादन साबित हो जाता है, इस तरह का आश्वासन वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हो सकता है शरीर। तत्काल मामले के तथ्यों में, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है। आईडीसीओ एक सांविधिक निकाय है और केवल निर्धारित तरीके से कार्य कर सकता है और मेंस्को को निर्धारित प्रारूप में निष्पादित किए जाने वाले पट्टा विलेख के बारे में सूचित किया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय विवादित निर्देश जारी नहीं कर सकता था।

22. रिट याचिका में, एक घोषणा की राहत देने के लिए प्रार्थना की गई थी कि मेंस्को ने संपत्ति पर कब्जा करने के लिए पूरा अधिकार हासिल कर लिया है। कब्जे की

तारीख से 99 साल की अवधि के लिए विचाराधीन है और आईडीसीओ ने उक्त भूमि पर अपना अधिकार खो दिया है और उसके पास इसे पुनर्प्राप्त करने का उपाय है। मुकदमा दायर करके शेष राशि। प्रार्थना को पूरी तरह से गलत समझा गया था। तत्काल मामले में, समझौता ज्ञापन या आवंटन पत्र के आधार पर, मेंस्को को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, और यह अपने अनिवार्य हिस्से का प्रदर्शन करने में विफल रहने के कारण, समझौता ज्ञापन/प्रस्ताव अमान्य और अप्रवर्तनीय हो गया। जमीन को फिर से शुरू करने में आईडीसीओ पूरी तरह से उचित था।

23. उच्च न्यायालय ने शेष भूमि को पट्टे पर देने का निर्देश देते हुए खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है। उच्च न्यायालय ने इस बात को भी नजरअंदाज किया है कि कुछ हस्तक्षेपकारी घटनाएं हुई हैं और मेंस्को की ओर से अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से विफलता हुई है। उच्च न्यायालय नहीं कर सका बदली हुई स्थिति में और मेंस्को द्वारा किए गए चूक को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं। वास्तव में, मेंस्को कभी भी दिनांकित 4.7.2003 पत्र की शर्तों का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं था। कब पुनः प्रारंभ 25.7.2003 पर किया गया था, मेंस्को द्वारा 20.8.2003 पर एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया था। इसमें, भुगतान के लिए प्रार्थना की आड़ में अपनी शर्तें निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। वास्तव में, मेंस्को के आचरण से यह स्पष्ट है कि इसका किसी भी बिंदु पर कोई औचित्य नहीं था। पट्टा विलेख निष्पादित न करने का समय। यह के लिए भी देरी कर रहा था। इसके लिए सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारण जो पूरी तरह से अस्वीकार्य आचरण थे, विशेष रूप से कब्जा करने के बाद। उल्लंघन को कई वर्षों तक ठीक नहीं किया गया था, बहुत कम तीन महीनों के लिए जिसमें इसे ठीक किया जाना था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने आईडीसीओ की कार्रवाई को रोकने का दुस्साहस किया भूमि को फिर से शुरू करना अवैध होगा। इसमें प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई न्यायसंगत या कानूनी विचार नहीं किया

गया था और अवैधता को लागू करने के लिए एक रिट जारी नहीं की गई है। न केवल मेंस्को का आचरण अनुचित था, बल्कि तीसरे पक्ष के अधिकारों ने भी हस्तक्षेप किया था। भूमि को फिर से शुरू करने और कब्जा सौंपने के पत्र को रद्द करने के लिए कानूनी तरीके का उपयोग किया गया था।

24. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। अपीलों की अनुमति है। रिट याचिका बनी हुई है बर्खास्त कर दिया। मेंस्को द्वारा आज से दो महीने की अवधि के भीतर आईडीसीओ को 5 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण :** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।